भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3907

सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

देश में रोजगार की स्थिति

3907. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि आर्थिक विकास के दावों के बावजूद हाल के वर्षों में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने कुछ रोजगार सर्वेक्षणों को बंद या संशोधित किया है, जिससे देश में नौकरियों के आंकड़ों की पारदर्शिता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बेरोजगारी दर का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर केरल का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ड) वर्तमान में केंद्र सरकार के विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में रिक्तियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि भर्ती में देरी ने शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी को और बदतर कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(छ) क्या राज्यों ने रिक्तियों को भरने के लिए अनुमति या सहायता मांगी है, लेकिन उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में सभी स्वीकृत पदों को भरने के लिए समयबद्ध योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0%, वर्ष 2018-19 में 5.8%, वर्ष 2019-20 में 4.8%, वर्ष 2020-21 में 4.2%, वर्ष 2021-22 में 4.1%, वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 3.2% थी और इसी अवधि के दौरान केरल राज्य में यह दर क्रमशः 11.4%, 9.0%, 10.0%, 10.1%, 9.6%, 7.0% और 7.2% थी। पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (केरल सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) में रिक्त पदों का सृजन और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के निदेश दिए गए हैं। रिक्तियों और भर्तियों का विवरण केंद्र सरकार के तहत संबंधित मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा रखा जाता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध संगठनों और सीपीएसयू आदि द्वारा मिशन मोड में रिक्त पदों को भरा जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न शहरों में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से अक्टूबर 2022 से लाखों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।

*****